भारत सरकार

योजना मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2821

दिनांक 06.08.2025 को उत्तर देने के लिए

देश में आईटीआई

2821. **श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:**

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केंद्रीय और राज्य सरकार के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या नीति आयोग कौशल विकास के लिए एक नई रूपरेखा पर काम कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी आईटीआई को उद्योग मंडलों या कंपनियों को सौंपने संबंधी कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि नीति आयोग कौशल विकास रूपरेखा का पुनर्गठन करने की योजना बना रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या यह वर्तमान रूपरेखा से एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसके अंतर्गत सरकार सभी आईटीआई चलाती है और यदि हां, तो इस कदम के क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय;
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) योजना मंत्रालय एवं
राज्यमंत्री, संस्कृति मंत्रालय

(राव इंद्रजीत सिंह)

(क) कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) के तत्वावधान में प्रशिक्षण महानिदेशालय (डीजीटी) देश के युवाओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के देशव्यापी नेटवर्क के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) का क्रियान्वयन करता है। वर्तमान में, देश भर में 14,615 आईटीआई स्थापित हैं, जिनमें से 3,316 सरकारी आईटीआई और 11,299 निजी आईटीआई हैं, राज्यवार सूची नीचे तालिका में दी गई है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य सरकार आईटीआई की संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	3
2	आंध्र प्रदेश	85
3	अरूणाचल प्रदेश	7
4	असम	31
5	बिहार	150
6	चंडीगढ़	2
7	छत्तीसगढ़	120
8	दिल्ली	18
9	गोवा	11
10	गुजरात	273
11	हरियाणा	159
12	हिमाचल प्रदेश	128
13	जम्मू और कश्मीर	49
14	झारखंड	77
15	कर्नाटक	274
16	केरल	149
17	लद्दाख	3
18	लक्षद्वीप	1
19	मध्य प्रदेश	195
20	महाराष्ट्र	422
21	मणिपुर	10
22	मेघालय	7
23	मिजोरम	3
24	नागालैंड	9
25	ओडिशा	73
26	पुदुच्चेरी	8
27	पंजाब	115
28	राजस्थान	182
29	सिक्किम	4
30	तमिलनाडु	93
31	तेलंगाना	66
32	दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव	4
33	त्रिपुरा	20
34	उत्तर प्रदेश	294
35	उत्तराखंड	103
36	पश्चिम बंगाल	168
कुल		**3,316**

(ख), (घ) और (ङ) नीति आयोग, भारत सरकार के सर्वोच्च लोक नीति थिंक टैंक के रूप में दीर्घकालिक नीतिगत ढाँचे विकसित करता है और केंद्र तथा राज्य सरकारों को कौशल विकास के क्षेत्र सहित कार्यनीतिक एवं तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान करता है। जनवरी 2023 में, इसने "औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) का रूपांतरण" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की। यह रिपोर्ट शासन और प्रशासन, बुनियादी ढाँचे, पाठ्यक्रम, वित्तपोषण, रिपोर्टिंग और निवारण, साझेदारी और छात्र सहायता सेवाओं में बदलाव से संबंधित सात-आयामी दृष्टिकोण के माध्यम से आईटीआई को बदलने की सिफारिश करती है।

(ग) मई 2025 में, मंत्रिमंडल ने देश में व्यावसायिक प्रशिक्षण की समग्र गुणवत्ता और प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के उन्नयन और पांच राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई) की स्थापना के लिए एक राष्ट्रीय योजना को मंजूरी प्रदान की है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

i. आईटीआई में प्रशिक्षण वितरण की गुणवत्ता में सुधार करना;
ii. उद्योग मानकों के अनुसार बुनियादी ढांचे और उपकरणों का आधुनिकीकरण करना;
iii. विशेष रूप से नए और उभरते क्षेत्रों में, उद्योग-संरेखित दीर्घकालिक और अल्पकालिक पाठ्यक्रम शुरू करना;
iv. मांग-आधारित कौशल विकास और बेहतर रोजगार परिणामों के लिए उद्योग संपर्क को मजबूत करना; और
v. व्यावसायिक शिक्षा में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और लीडरशिप के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों (एनएसटीआई) की क्षमता में वृद्धि करना।

योजना के अंतर्गत, प्रासंगिकता और परिणाम-आधारित वितरण सुनिश्चित करने के लिए एंकर उद्योग भागीदारों (एआईपी) के साथ साझेदारी में गठित विशेष प्रयोजन वाहनों (एसपीवी) के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाएगा।

*****